(ग) समाजिक वानिकी और फार्म वानिकि के अंतर्गत वृक्षारोपण जवाहर रोजगार योजना के कार्यों की एक स्वीकार्य मद है। तथापि, सरकार का दस लाख कुओं के निर्माण की योजना के अंतर्गत निर्मित कुओं के आस-पास 10 वृक्षों के रोपण को अनिवार्य बनाने का कोई विचार नहीं है।

बिहार में आदिवासी खेतिहर मजदूर

*2414. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1992 के "दि डेली टेलीग्राफ" में "एक्यूट पावर्टी इन ट्राइबल बिहार" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी खेतिहर मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन आदिवासी कर्मकारों का शोषण समाप्त करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष योजना शामिल की गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा गठित अध्ययन दल ने बिहार में ग्रामीण असंतोष के बारे में किए गए त्वरित अध्ययन की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि "यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण असंतोष की जड़ मुट्ठी भर शोषणकारी भूस्वामियों द्वारा बहुसंख्यक मेहनती भूमिहीनों का शोषण और दमन करना है"

(ग) और (घ) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने आदिवासी विकास के समूचे प्रश्न की समीक्षा की थी। कार्यदल ने सिफारिश की थी कि एक समन्वित नीति पर आधारित संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास पर मुख्य बल दिया जाना चाहिए और सामान्य सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से भिन्न इस तरह के विकास कार्यक्रम बनाए जाने चाहिएं कि इनसे आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों में व्याप्त प्रमुख समस्याओं का दिनान हो सके। अन्य बातों के साथ-साथ कार्यदल ने यह भी सिफारिश की थी कि आदिवासी समुदायों को हर तरह के शोषण से बचाया जाना चाहिए जिसके लिए कार्यदल ने कई उपायों की सिफारिश की है जिनमें भूमि के हस्तांतरण को रोकना तथा पहले से अंतरित भूमि की वापस बहाली और बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिये कानून बनाना शामिल है।

गुजरात में ग्रामीण विकास परियोजनायें

2915. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ग्रामीण विकास परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए वर्षवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ;

(ग) गुजरात के किन-किन जिलों में ये परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं ; और

(घ) इन सभी परियोजनाओं को उनके निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) केन्द्र में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के जिलावार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।